A = B =

बचत → निवेश — { पशुधन, मशीन, भवन, उपकरण }

$$g = S \times \frac{1}{Cr}$$

$$g = \frac{S}{Cr}$$

S → Saving Rate

प्रस्तावना -

सरकारी बजटिंग में सरकारी बजट के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ का अध्ययन किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि बजट प्रस्तुतीकरण का प्रारम्भ निर्णायक रूप से कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण ( Financial Control ) स्थापित करता है।

(i) Line-Item Budgeting -

इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का प्रस्तुतीकरण मंत्रालयानुसार (और इनके अन्तर्गत विभागानुसार) किया जाता है।

चूँकि, मंत्रालय Line संस्थायें मानी जाती हैं, इसलिये इस प्रकार की बजटिंग को लाइन-आइटम बजटिंग कहते हैं।

इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाने के लिए पिछले वर्ष के खर्चों को मुख्य रूप से आधार बनाया जाता है।

↓

ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अनुकरण।

↓

खर्चों का उचित आधार नहीं।

इसके अलावा,

खर्चों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

↓

इसके अन्तर्गत, मंत्रालय और विभाग अपनी अलग-अलग गति-विधियों (जिन्हें तकनीकि रूप से प्रोग्राम कहा जाता है।) के लिए अलग-2 लागत बजट (Cost - Budget) तैयार करते हैं जिन्हें एक प्रकार से मिनी बजट कहा जा सकता है।

(i) Study – ₹5,000

(ii) Residence – ₹3,000

(iii) Food – ₹3,000

(iv) others – ₹9,000

₹20,000

ग्रामीण विकास मंत्रालय

↓

ग्रामीण विकास विभाग

↓

प्रोग्राम बजटिंग

↓

(i) ग्रामीण आवास —

(ii) ग्रामीण सड़कें —

(iii) ग्रामीण रोजगार —

इस सेटिंग में कार्यपालिका पर संसदीय नियन्त्रण मजबूत होता है।

↓

एक मुख्य कमजोरी → निष्पादन को लेकर कार्यपालिका को उत्तरदायी / जवाबदेह नहीं बना पाती है।

वाले खर्च के सामने उद्देश्यों का विवरण देते हैं।

↓

उदाहरण : ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए माँगे जाने वाले किसी खर्च के सामने यह लिखेगा कि वह कितने घरों का निर्माण करेगा। आदि।

Note : भारत में 2005-06 में लागू की गई Outcome Budgeting इस बजटिंग से समानता रखती है।

बजट - २०१८-१९

↓

ग्रामीण विकास विभाग

- **Outlay** (खर्च का स्तर) → ₹23,000 Crore
- **Output** (भौतिक लक्ष्य/परिणाम) → ५७ लाख घरों का निर्माण।
- **Outcome** (गुणात्मक लक्ष्य/परिणाम) → ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार।

सरकारी योजनाओं का Governance ↑

Performance Budgeting से कार्यपालिका को निष्पादन के सन्दर्भ में उत्तरदायी बनाने में मदद मिलती है।

लेकिन –

**कमजोरी** → गुणात्मक क्षेत्रों में इसे लागू करना कठिन होता है।

↓

कारण → मापनीय लक्ष्य तय करना कठिन।

(iv) ZBB = Zero Base Budgeting

↓

इसमें मंत्रालय / विभाग

एकदम नये सिरे से

मूल्यांकनों और रिसर्च

प्रस्तावना -

- शुरुआत - आस्ट्रेलिया।
- भारत - 2005-06

यह कोई अलग प्रकार की बजटिंग नहीं जो कार्यपालिका की जवाबदेही को निर्धारित करती हो।

इसमें यह दिखाया जाता है कि बजटीय खर्च का कितना भाग महिलाओं के विकास से मुख्य रूप से जुड़ा है।

↓

आवश्यकता -

कोई भी बजट

↓

Gender - neutral

लिंग - निरपक्ष

↓

लेकिन बजट के प्रभाव

↓

Gender - neutral नहीं हो

**Note** –

भारत में प्रतिवर्ष संसद में **GBS** (Gender Budget Statement) प्रस्तुत किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं –

Part - A

↓

100 % महिलाओं से जुड़े खर्चे ।

Part - B

↓

ऐसे खर्चे जिनका कम से कम 30 % भाग महिलाओं से सम्बन्धित हो।